

जानकारी है अभी आपने कहा था कि सारे बिहार में डाकखाने खोल दिए गये हैं, ऐसी स्थिति नहीं है बल्कि सच बात यह है मैंने जो मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता रहा हूँ कि पिछले मंत्री जी ने बताया था कि बिहार की पंचायतों से कहा गया कि वे सहयोग करें ताकि वहाँ के गांवों तक चिट्ठियाँ पहुँच सकें। अब आपकी नीति क्या है, वास्तविकता क्या है? योजना आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि पंचायतों से सहयोग लेकर डाकखाने खोलने की बात कही गई थी लेकिन उसमें सरकार को सफलता नहीं मिल रही है। कृपा करके स्थिति स्पष्ट करें।

श्री बलवन्त सिंह राम्वालिया: मैंने यह नहीं कहा कि बिहार के सभी गांवों में डाकखाने खोल दिये हैं। मैंने यह कहा था कि सभी गांवों में...

श्री नरेन्द्र मोहन: आप कृपा करके यह बता दें।

उपसभापति: बोलने दीजिये। वे अभी पूरा करेंगे।  
नरेन्द्र मोहन जी, लैट हिम स्पीक।

श्री बलवन्त सिंह राम्वालिया: नरेन्द्र मोहन जी, मैं तो यह अर्ज की थी कि जो टोटल विलेज है, हमने उनमें से बिहार के 1,36,237 रूरल एरियाज का क्लेम बताया था उसमें से केवल 11,063 ही खोल सके। जब श्री अहलुवालिया जी ने कहा कि आप गांवों की उपेक्षा कर रहे हैं तब मैंने निवेदन किया था कि गांव में तो हमने 11,063 और शहरों में 726 किये हैं। यह मैंने अर्ज की थी। अब आप जी ने कहा कि गांवों की पंचायतों का इन्वाल्व करके कुछ आगे बढ़ने का यत्न किया था। वह हमने खुशी से नहीं किया। हमारी मजबूरी यह थी कि हमने जितने प्रोजेक्ट नये डाकखाने खोलने के भेजे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिये। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर दे तो हाथ पर हाथ रखकर तो बैठा नहीं जा सकता, कुछ तो करना होगा। फाइनेंस की भी मजबूरी रही होगी। उनकी मजबूरी है तो हमारी आपसे मजबूरी है।

श्री नरेन्द्र मोहन: मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

उपसभापति: देखिये, मामला मजबूरी का हो गया है। (Interruptions) Mr. Narendra Mohan, no. I have not identified you.

#### Security for Delhi Police Officials

\*443. DR. RANBIR SINGH:†

SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Police Officers of Delhi have been provided security personnel without approval of protection Review Samiti of the Ministry;

(b) whether Government propose to take action against those officials who are responsible for providing security personnel without approval of competent authority; and

(c) if so, the details thereof; and if not, the reasons for such misuse?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA):  
(a) Yes Sir.

(b) and (c) Delhi Police have informed that they have provided such security to 5 Delhi Police Officers who are handling sensitive duties and are required to take stringent action against criminals and the underworld elements. This security has been provided keeping in view the threat perceptions in their cases. These cases will be got reviewed and further action will be taken on the basis of fresh threat assessment in their cases.

डॉ० रणबीर सिंह: मैडम, ये बड़ा प्वाइन्ट क्वेश्चन था।

(a) Whether it is a fact that some Police Officers of Delhi have been provided security personnel without approval of Protection Review Samiti of the Ministry;

इसका जवाब यस है। दूसरा भी बहुत प्वाइन्ट क्वेश्चन था।

(b) Whether Government propose to take action against those officials who are responsible for providing security personnel without approval of competent authority.

जिसके जवाब में, इनका जवाब नहीं है। क्या एक्शन

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ranbir Singh.

उनके खिलाफ लिया जा रहा है, इसके लिए यह जस्टीफिकेशन देने की कोशिश की है। हमने जस्टीफिकेशन नहीं पूछा हमने यह पूछा कि अगर यह गलती हुई है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। इसका जवाब नहीं आया। मैं चाहूँगा कि इसका जवाब मिलना चाहिये। हमने जस्टीफिकेशन पूछा ही नहीं कि कितना जस्ट है सिक्युरिटी देना This was not the question. क्वेशन यह है कि उनके खिलाफ जिन्होंने गलत तरीके से सिक्युरिटी प्रोवाइड की है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है या क्या एक्शन प्रोपोज्ड है, इसका जवाब चाहिये। I think the Minister should say something.

**SHRI INDRAJIT GUPTA:** Madam, there is a little bit of confusion here because the question is who has to give the approval or who is the authority who has to sanction the posting of security personnel in the case of police officers in Delhi. Well, as far as police officers are concerned, I am informed that the authority is the Commissioner of Police, Delhi, and nobody else. He has got the authority and power to decide which of his officers should be provided with security arrangements. Madam, I would like to inform the House that at the moment out of 300 officers in the Delhi Police, only five have been provided with security. As far as other people are concerned, not police officers, but other VIPs or important, eminent, people or Members of Parliament or Ministers and so on, who are provided with security, that is sanctioned on the basis of whatever reports we receive from the Intelligence Branch regarding threat perception to these people. All cases are referred to the IB. They have got a Review Committee of their own and on the basis of assessment received from them the security arrangements are made. In the case of police officers, it is not referred to the IB. It is at the discretion of the Commissioner of Police.

**डा० रणबीर सिंह:** यही जवाब अगर इस में दे दिया जाता।

**उपसभापति:** अच्छा अब आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये।

**डा० रणबीर सिंह:** दूसरा सवाल यह है कि क्या क्राइटेरिया है सिक्क्युरिटी देने का लोगों को और जनरल लोगों को पुलिस का तो आपने बताया। मेरा इसमें कहना यह है कि जैसे आज ही के अखबार में यह आया है कि 56 करोड़ से ज्यादा रुपया खाली दिल्ली में वी०आई०पी० सिक्क्युरिटी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी सिक्क्युरिटी मिली हुई है जिनकी मैं ज़रूरत नहीं समझता या थोड़े दिन पहले जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। खाली दिल्ली में 56 करोड़ रुपया सिक्क्युरिटी पर खर्च किया गया, मैं समझता हूँ कि यह वेस्टफुल एक्सपेंडीचर है। हम बाहर से कर्ज ले रहे हैं और वेस्टफुल एक्सपेंडीचर कर रहे हैं। हम अपना वेस्टफुल एक्सपेंडीचर रोक नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ वैसी हो गई जैसे एक शेर है—

कर्ज की पीते थे मय

कहते थे कि रंग लाएंगी हमारी फ्राक मस्ती एक दिन।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस वेस्टफुल एक्सपेंडीचर को रोकने के लिए क्या कोई प्लान गवर्नमेंट कर रही है, अगर है तो वह क्या है?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** उपसभापति महोदया, इस पूरे इंतज़ाम को रिव्यू किया जा रहा है। मैं भी जानता हूँ जो आज अखबार में निकला है कि 56 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वी०आई०पी० और वी०वी०आई०पी० की सिक्क्युरिटी के लिए। मैं समझता हूँ कि इस तथ्य के प्रकाशित होने से पब्लिक को भी धक्का लगेगा कि इतने बड़े पैमाने पर जो खर्च किया जा रहा है इंडीविजुयल्स को, वी०आई०पी० को और वी०वी०आई०पी० को सिक्क्युरिटी देने के लिए। 56 करोड़ रुपया कोई छोटी बात नहीं है। हम समझते हैं कि यह जो पूरा इंतज़ाम अब चल रहा है इसका एक रिव्यू होना चाहिये।

हम रिव्यू शुरू कर रहे हैं और रिव्यू करके हम देखेंगे उन केसेज़ में जहाँ हम समझते हैं कि जो सिक्क्युरिटी दी गई है, वह जारी रहनी चाहिये तो वह जारी रहेगी, अगर घटाने की ज़रूरत है तो हम घटाने की सिफारिश करेंगे और अगर बिल्कुल पूरी की पूरी हटा लेने की सिफारिश आती है तो हम वह करेंगे। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि मेरे इस मंत्रालय में आने के बाद मैंने एक बार शुरू शुरू में कोशिश की थी। मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, ऐसे काम करता रहता हूँ जिससे मुझे मुश्किल में पड़ना पड़ता है। मैंने एक बार आने के बाद यह काम शुरू किया था, कोशिश की थी। आजकल मैडम बहुत लोग मजाक में

हो था जो कुछ भी हो वे कहते हैं कि यह सिक्वोरिटी स्टेटस सिम्बल हो गया है। मैं नहीं जानता हूँ। कोई इसको स्टेटस सिम्बल समझे या कुछ भी समझे लेकिन यह बात ठीक है कि यह थ्रेट का जो परसेप्शन है इसको बहुत होशियारी के साथ मापना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जिनको थ्रेट है, खतरा है। उनको सिक्वोरिटी नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं आता। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में कभी कभी शक होता है कि उनको कितना थ्रेट है। ऐसे किस के लोग हैं जो हो सकता है कि अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में या अपने जिले में... (व्यवधान)...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: उनके दो सौ रूपए सिक्वोरिटी एलाउंस दे दीजिए... (व्यवधान)...

श्री इन्द्रजीत गुप्त: वह भी सवाल आ जाएगा कि आपको जो सिक्वोरिटी दी जाएगी उसके खर्च का एक हिस्सा उस आदमी को वहन करना पड़ेगा। अभी हुआ नहीं है। अभी कोई ऐसा डिजिजन नहीं हुआ है... (व्यवधान)... मैं बोल रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ। एक मेम्बर ने, वे काफी पुराने मेम्बर हैं, उनके यहां, उनके मकान के बाहर जो सिक्वोरिटी गार्ड, स्टेशनरी, स्टेटिक गार्ड दिया गया था उसको उठा लेने की बात जब चली तो वे बहुत बिगड़ गए। लोग ऐसे बिगड़ जाते हैं अगर कहा जाए कि इनको हटिया जाए। तो वे मेम्बर साहब मेरे पास आए। मैंने कहा कि मुझे आप समझाइए जरा कि कौन आपको मारने के लिए अभी आ रहा है, कहां से आप महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा खतरा आपको है। उन्होंने कहा कि नहीं रात को जब मैं वापस आता हूँ, बाहर जाने के बाद जब घर वापस आता हूँ तो मेरे मकान का फाटक कौन खोलेंगा। फाटक खोलने के लिए एक आदमी चाहिए। मैंने कहा कि यह तो अजीब बात है आप अपने जेब से खर्च करके चौकीदार रखिए जो फाटक खोले। इसके लिए सिक्वोरिटी का आदमी हम खर्च करके रखें यह तो नहीं चल सकता है...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: You deserve all support in your efforts... (interruptions)...

श्री इन्द्रजीत गुप्त: तो मैडम, मैं इतना ही अभी कह सकता हूँ कि पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक भी इसके साथ है और ज्यादातर मेम्बरों का कोआपरेशन इसमें जरूर मिलेगा मैं आशा करता हूँ और फिर यह हालत इस ढंग से नहीं रहेगी।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, I request you to club Question Number 456 with this. It is about police complaints authorities in States and Union Territories.

उपसभापति: साल्वे साहब अभी इसमें कुछ रह गया है। अभी तो कुछ रहा नहीं। उन्होंने कह दिया कि रिव्यू कर रहे हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे: मैडम, मैं कुछ और कहना चाहता था... (व्यवधान)...

उपसभापति: आपका नहीं, उनका भी है but I am just asking Mr. Salve whether there is any question. I am just asking the House because the question is there. There is no need that everybody give his name and ask question which is already answered or to which he has no answer. But, since your name is there, if you want to add something you can, which may help him. But there is no point in having the question again.

श्री रामनाथ कौचिन्द: मैडम, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में, अभी जो यहाँ सदन में दिया, उसमें बताया कि दिल्ली कमिश्नर आफ पुलिस को यह अख्तियार है कि वह किन अफसरों को सिक्वोरिटी परसोनल दे सकते हैं। मेरा प्रश्न जो था उसमें मेरा यह कहना था कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति बनी है प्रोटेक्शन रिव्यू समिति उसके तहत सिक्वोरिटी परसेप्शन एपूव होते हैं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में माना है कि वह गृह मंत्रालय की समिति है। लेकिन आज सदन के अंदर माननीय मंत्री जी ने दूसरा बताया। हम इसको क्या मानकर चलें कि मेरा प्रश्न गृह मंत्रालय की समिति से है अथवा दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत जो समिति बनी हुई है उससे है। पहले तो मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। दूसरा इसी से मेरा पूरक प्रश्न है। उसका पार्ट 'ए' यह है कि जो 5 अफसरों को सिक्वोरिटी दी गयी वे कौन-कौन से अफसर हैं और उनको कब से यह सिक्वोरिटी बराबर दी जा रही है? क्या उनका दिल्ली पुलिस के बाहर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है? मेरी जानकारी के मुताबिक वे जो सेंसिटिव मैटर डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, अब नहीं भी कर रहे हैं लेकिन अभी भी सिक्वोरिटी परसोनल्स उनके पास हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** The first part of the question you have answered, but perhaps it was not very clear to the hon'ble Member.

**SHRI INDRAJIT GUPTA:** Madam, as far as the Review Committee is concerned, there is one Review Committee in the Ministry with some senior officers in it. That Review Committee does not go into the cases of police officers who are required to get personal security. That is a Committee which is confined to the cases of people other than police. Those cases are referred to that Committee. We get so many representations. I get representations practically every day from somebody or other. They are dealt with by that Committee. As far as the police officers are concerned, I have already explained that this is the prerogative of the Police Commissioner of Delhi to decide it. It is according to his decision that these five police officers have been provided security. The hon'ble Member wanted to know their names. I can give their names if you like.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** If it is not secret, you can give the names. I mean, if it is not going to cause any problem to them, you can give the names.

**SHRI INDRAJIT GUPTA:** That is not necessary because this decision was taken by police as there was threat perception. There is no point in giving those names and making them more vulnerable.

**SHRI INDRAJIT GUPTA:** Madam, the hon'ble Member, towards the end of his question, wanted to know whether among these officers there is any such officer about whom, may be there was a threat perception earlier and he was given security, and even when the situation has change now, he is still given security. So far as I know, there is no such case among these five officers. There are people who have been deployed to tackle terrorist and such kind of people in Delhi. They are supposed to be on their trail, tracking them, sometimes have en-

counters with them and so on. That is why they have been given security.

**SHRI N.K.P. SALVE:** Madam, my question emanates from a larger angle of security which the Home Minister referred to. The threat perception angle is a very relevant angle in providing security. But, there cannot be an objective and tangible evaluation of this sort of a threat. Also he has very rightly said that some people want security as a measure of status symbol, which is superfluous at the public cost. But, in view of the deteriorating law and order situation in Delhi as we hear of rape, murder and kidnapping every day.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** And bomb blast.

**SHRI JOHN F. FERNANDES:** And cylinder blast.

**SHRI N.K.P. SALVE:** Yes, whatever it is I mean I do not blame you for that at least. You are not doing it. So, I am entitled to your gratitude on this. Madam, my question is very simple. Where people do feel unsafe may be in Bangalore or else where in any remote places, it is not possible for you to evolve some sort of arrangement in terms of which people are willing to pay for it. You provide them the police security.

**SHRI INDRAJIT GUPTA:** Madam, I have already stated that the whole system is under review and only when we have worked some new alternative scheme, I will come before the House, if you like, and make a statement. Also, I may say that I would welcome any specific suggestions or proposals from hon'ble Members which they can send to House to make this scheme more efficient and more effective, but also less expensive for the tax-payers.

**SHRI JOHN F. FERNANDES:** Madam, the national capital, Delhi is said to be the No. 1 crime city in the country. We can understand the gravity of the situation from this question itself which talks about security for Delhi Police offi-

cials. We can understand the gravity of the situation when we find that even police officials need security. Among all the cities in the country, Delhi is on the top, as far as crime is concerned.

In this connection, I would like to point out that the former Prime Minister, Shri Deve Gowda, made a statement in this House, emotionally, that he would start a special cell in the Delhi Police to fight crimes. May I know from the hon. Home Minister whether anything has been initiated in this regard so that the people of Delhi can have the confidence that their lives would be protected?

SHRI INDRAJIT GUPTA: I am not very clear as to what exactly the former Prime Minister had committed in this House. But one proposal which came up was that there should be a set-up in Delhi, a police complaints authority, which would be independent of the Government; an autonomous body—not of officials—to which the members of the public can go and lodge their complaints against misbehaviour or malpractices or oppression by the police, or, failure on the part of the police in the various *thanas* and all that to register cases—take FIRs. etc. — or, complaints against the police of misbehaviour towards women when they go to the *thanas* to report certain cases. This complaints authority is in the process of being formed.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, I am not referring to that authority. I am referring to the special crack cell in the Delhi Police about which the former Prime Minister announced in this House. (*Interruptions*) If the hon. Minister does not have any information on this, he can get the information.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: The hon. Member is talking about the special task force. (*Interruptions*)

SHRI JOHN F. FERNANDES: The former Prime Minister made an announcement in this House that he would start a special police cell to fight crimes in the capital. He announced it in this

House, Madam.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Police cell?

SHRI JOHN F. FERNANDES: Special police cell. Special police cell to fight crimes.

SHRI SATISH AGARWAL: Special task force. (*Interruptions*)

SHRI INDRAJIT GUPTA: Madam, this complaints authority, in my opinion, when it starts functioning, would be more comprehensive and more effective than some police cell. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, what I understand is that the former Prime Minister said on the floor of this House that there would be a special task force which would act like a crack force to deal with such nefarious activities.

SHRI N.K.P. SALVE: Criminal activities.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHARAO SHINDE: Madam, please permit me.

SHRI INDRAJIT GUPTA: About the proposal made by the former Prime Minister in regard to the setting up of a special task force, I am aware of that. But it ran into some difficulties because there were some authorities and agencies in Delhi who were not clear as to what exactly this task force was supposed to do; whether it would become some kind of a parallel or a rival body to the existing police agencies. There was a big debate. There was a quarrel, there was a dispute, about all this. It was not also further clarified by the Government. Therefore, I am afraid, that matter, at the moment, has not taken off.

As far as the police complaints authority is concerned, within a month or so, it would be constituted and I would report it to the House.

SHRI JOHN F. FERNANDES: This tantamounts to an assurance to this House, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know, but let him find out.

SHRI N.K.P. SALVE: He has said that the proposal in regard to the setting up of a special task force has run into difficulties. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are so many names. I do not know how the Hon Minister is going to answer. (*Interruptions*) I know everybody is concerned, the whole House is concerned, about it. But we have other questions too. Shri Peter Alphonse. (*Interruptions*) Mr. Shinde, please sit down. I have called Shri Alphonse. He is standing behind you. You cannot see him.

SHRI PETER S. ALPHONSE: While I thank the most outspoken Home Minister we have ever had for having admitted that security cover has become more a political status symbol than a measure intended to ensure the safety of the people concerned, I would like to know from the hon. Minister whether the Government could, at least, reduce the expenditure incurred on providing security cover to these people when they go on frequent travels, the 'Z' category persons, ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has already answered that. (*Interruptions*) He has answered it.

SHRI PETER S. ALPHONSE: He has not answered.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot waste the time of the House. Please sit down.

SHRI PETER S. ALPHONSE: Madam, my point is that...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. (*Interruptions*) Don't put questions which have already been answered. There are other Members. (*Interruptions*) Please sit down. I have other names. Shri Shinde, please.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे: मैडम, यह बात सही है कि सोशल वर्कर, पॉलीटीशियंस को सेक्युरिटी कवर मिलती है, लेकिन जब पुलिस के सदस्य

टैरिज्म से कड़ा मुकाबला करते हैं तो उन की भी लाइफ को रिक होती है और जब किसी पुलिस ऑफिसर के लिये सेक्युरिटी कवर चाहिए होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट की पुलिस होम मिनिस्ट्री को लिखना पड़ता है, फिर उस में काफी वक़्त लग जाता है। मैडम, जब वह अपनी जान लगाकर देश की सेवा करते हैं तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की सेक्युरिटी के लिए इमीडिएट कुछ सेक्युरिटी कवर देते हैं तो यह ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप के कानून में या रूल्स रेगुलेशंस में रिजिडेंसी है, उस रिजिडेंसी को यदि फ़ैक्टिसबल बना दें या जैसाकि सम्मानित सदस्य श्री साल्वे जी ने कहा कि सेक्युरिटी रखना प्रिस्टीजियस हो गया है, तो इस के लिए हम कहते हैं जैसे कि...

Mr. Ribeiro was given full security. But that was permitted by the Government of India because he was fighting against terrorism. Just as in Delhi, Bombay and other places, they should be permitted to immediately allow security for a particular period. There should not be any hue and cry saying why police officers should get such security. Is there anything for the Home Ministry of the Government of India to say on this count?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a suggestion.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: I think the Home Minister should enlighten us.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I do not see why there should be any delay in such cases, because the hon. Member has referred to Bombay, Madras and such cities. It is a question of empowering the Police Commissioners or the police authorities of those cities to give security to whichever police officers are considered to be in danger or under threat. But I will look into this matter again; I don't think there is any difficulty about it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, the hon. Minister has spoken of threat perception, security problem, bomb blasts and all that. I quite

appreciate the concern of the Government for the problems of the VVIPs, VIPs and others. But the question is, the threat perception is also there so far as the corporate life, collective life, of the people of Delhi is concerned. It is on the increase. Threat perception to normal human life in Delhi is on the increase. Therefore, while considering the question of reviewing the system regarding provision of security to the VVIPs, what is the Government doing to review the protection of the common people, including the question of collusion of a large number of policemen with the criminals in Delhi?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: All over India.

SHRI INDRAJIT GUPTA: It is a much bigger question, Madam—I can't just reply offhand to that. It is the job of the police to provide better protection to all citizens in the country, and wherever there are lapses—and there are lapses—all those are being looked into. Certainly I think that VIPs and VVIPs are, at the moment, in the name of security, in my opinion, getting many facilities and safeguards which are denied to the ordinary people. It is a fact. Ordinary people feel that there is no security for them whereas a few hundred people, who are VIPs, are being given all these things. So, that is the part of the review that we are going to carry out. I may also say—there was a question there—that we are very much tackling, at the moment—the Prime Minister spoke about it here the other day—the problem of these convoys of vehicles which belong to VIPs and VVIPs, going from somewhere to somewhere. I think Mr. Sikander Bakht had raised it that day. The whole road is closed for half an hour or 45 minutes, holding up traffic and causing a lot of trouble to the ordinary people. This is one of the things that we are certainly going to look into and try to modify and change. It doesn't happen in other countries. There is no reason why it should happen always in our country only. The

British Prime Minister, when he goes from Downing Street to his office, has two guards only with him, one motor cyclist in front of his car and one at the back. And when he comes to a traffic light, the man in front goes to the back, the man in the back comes in front and then they go on again. But here we block the road for half an hour, 45 minutes, with crowds of security people all around the VIP. I think it certainly calls for a substantial change and modification.

SHRI R.K. KUMAR: Madam, kindly allow me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. He has replied enough.

SHRI R.K. KUMAR: I have given my name.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know that you gave your name. But I am sorry.

SHRI R.K. KUMAR: There is a question about Members living in South Avenue. ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI R.K. KUMAR: Madam, I walk out.

*(At this stage, the hon. Member left the Chamber)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I must tell the Members that we have to have a certain limit on supplementaries. If we keep on asking supplementaries on one question, we will not be able to take up other questions. Don't have 20 questions listed in the Business. Have five only. Why waste the time of the Secretariat and the Government?

\*444. *[The Questioner (Shri Sushil Barongpa) was absent for answer vide column..... infra]*

Representation from the Cement Manufacturers' Association, New Delhi

\*445. SHRIMATI VEENA VERMA:†  
SHRI SUSHIL KUMAR SAM-  
BHAIRAO SHINDE:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

†The Question was actually asked in the House by Smt. Veena Verma.